

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मैं माननीय सदस्य महोदय को बहुत विनम्रता से बताना चाहूँगा कि अगर वे मेरे इस उत्तर के Statement-I को विस्तार से पढ़ेंगी, तो NIELIT ने 4 लाख लोगों को train किया है, C-DAC ने 5 हजार लोगों को train किया है और 1,500 को हम PhD दे रहे हैं। अगर आप इसके Statement-I के III को देखें, तो 2,29,700 candidates Skill Development में enrol हुए, जिनमें 1,81,316 train हो चुके हैं। अब यह प्रदेशवार कितना है, मैं आपको इसकी सूची भेज दूँगा। एक बात अवश्य है कि Digital India की व्यापकता में प्रदेश और केंद्र, दोनों को साथ-साथ मिल कर चलना है। इस दिशा में राज्यों को जो भी सहयोग चाहिए, वह हम अवश्य देंगे।

रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित सीढ़ियां और लिफ्ट लगाया जाना

*20. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उज्जैन, रतलाम, इन्दौर, भोपाल (मुख्य) इटारसी, नागपुर, जयपुर और कोटा सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर सुगमतापूर्ण ढंग से पहुंचने के लिए स्वचालित सीढ़ियां और लिफ्ट लगाए जाने की क्या-क्या योजना एवं कार्य-योजना है; और

(ख) उक्त रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की निरंतर बढ़ती संख्या के दबाव को विकेंद्रित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त स्टेशनों पर स्वच्छता और यात्री सुविधाओं को बढ़ाए जाने के लिए निरंतर किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय रेल की 770 एस्केलेटर और लगभग 620 लिफ्ट लगाने की योजना है जिसमें से अभी तक उज्जैन, रतलाम, इंदौर, भोपाल (मेन), इटारसी, नागपुर, जयपुर और कोटा सहित 167 स्टेशनों पर लगभग 370 एस्केलेटर और 98 स्टेशनों पर लगभग 183 लिफ्ट लगा दी गई हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	रेलवे स्टेशन	पहले से ही संस्थापित		योजना/कार्य प्रगति पर	
		एस्केलेटर	लिफ्ट	एस्केलेटर	लिफ्ट
1.	उज्जैन	—	4	2	—
2.	रतलाम	2	—	—	2
3.	इंदौर	—	1	6	1
4.	भोपाल (मेन)	2	1	—	2
5.	इटारसी	—	2	2	—
6.	नागपुर	2	—	4	—
7.	जयपुर	4	1	2	3
8.	कोटा	2	2	—	—

(ख) रेलें उपरोक्त उल्लिखित स्टेशनों पर निरंतर रूप से बढ़ती यात्री संख्या के दबाव को संभालने के लिए स्टेशनों को अपनी विभिन्न स्टेशन विकास योजनाओं के अंतर्गत निरंतर रूप से उन्नत कर रही हैं। आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत उज्जैन, रतलाम, इंदौर, इटारसी और जयपुर स्टेशनों की पहचान की गई है।

इन आदर्श स्टेशनों पर बढ़ते यात्री यातायात को संभालने के लिए निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं:

- परिचलन क्षेत्र में सुधार ताकि वाहनों आदि का उचित प्रवेश और निकास सुनिश्चित हो सके।
- बेहतर प्रकाश व्यवस्था के लिए लाइटिंग टॉवर।
- प्लेटफार्मों, कॉनकोर्स आदि पर बेहतर आधुनिक प्रकाश प्रबंध।
- साइनेज और कोच इंडिकेशन बोर्डों सहित यात्री मार्ग दर्शन अच्छी प्रणाली।
- बुकिंग और पूछताछ कार्यालयों में सुधार।
- बुकिंग कार्यालय, कतार लगाने के क्षेत्र आदि में रोशनी करना।
- यात्रियों के शीघ्र प्रवेश और निकास पर फोकस (बुकिंग कार्यालय सहित न्यूनतम दो प्रवेश और दो निकास स्थान)।
- स्टेशन परिसर में सुगम पहुंच।
- चौड़े पैदल पार पुलों का प्रावधान (एफओबी)।

निर्धारित मानकों के अनुसार उपरोक्त स्टेशनों पर सभी न्यूनतम आवश्यक सुख-सुविधाएं पहले ही उपलब्ध करा दी गई हैं। बहरहाल, यात्री सुख-सुविधाओं का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और कार्यों को आवश्यकता, यात्री यातायात के घनत्व आदि पर निर्भर करते हुए किया जाता है।

स्टेशनों पर स्वच्छता को बेहतर करने के लिए, 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था। तबसे रेलवे स्टेशनों सहित गाड़ियों और रेल परिसरों में स्वच्छता मानकों में महत्वपूर्ण और स्थायी सुधार के एकमात्र उद्देश्य के साथ भारतीय रेलों पर नियमित गहन अभियान चलाए गए हैं। स्वच्छता/सफाई के प्रति भारतीय रेल द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलकार्यों में से कुछ निम्नानुसार हैं:

- (i) सवारी डिब्बों में बाँयो-टॉयलेट लगाने की गति बढ़ाई गई हैं। पिछले दो वर्षों में 25000 से अधिक बाँयो-टॉयलेट फिट किए गए और इस वर्ष के लिए लक्ष्य 30,000 का है। सवारी डिब्बों में बाँयो-टॉयलेट लगाना यात्रा के दौरान मानव अपशिष्ट को सीधे पटरियों पर आने से रोकेगा।
- (ii) ऑन-बोर्ड क्लीनिंग की सुविधा को 780 से अधिक गाड़ियों में उपलब्ध कराया गया है जिसकी यात्री फीडबैक प्रणाली आधारित क्लोज्ड लूप 'एप्प' द्वारा निगरानी रखी जा रही हैं।

- (iii) रेलवे एसएमएस आधारित, वेब आधारित और एप आधारित शिकायत निपटान प्रणाली का उपयोग कर रही हैं। रोजाना अनियमित रूप से चुने गए लगभग 1 लाख यात्रियों से आईवीआरएस आधारित पैसेंजर फीडबैक लिए जा रहे हैं।
- (iv) प्रमुख स्टेशनों पर स्वच्छता प्रयासों के प्रभावों का आकलन करने के लिए 407 स्टेशनों पर स्वच्छता संसूचकों पर थर्ड पार्टी सर्वेक्षण किया गया जिसमें इस वर्ष 1.3 लाख यात्रियों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं।
- (v) यांत्रिक स्वच्छता उपकरण और गुणवत्ता वाली सामग्रियों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तरोत्तर रूप से प्रमुख स्टेशनों पर इंटीग्रेटेड हाऊसकीपिंग कांट्रैक्ट दिए जा रहे हैं।
- (vi) भुगतान करो एवं उपयोग करो शौचालयों सहित रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त शौचालय सुविधाएं।
- (vii) भारतीय रेल (रेल परिसरों पर स्वच्छता प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए जुर्माने) नियम, 2012 को लागू करना तेज किया गया है।
- (viii) प्रमुख स्टेशनों पर स्वच्छता गतिविधियों की निगरानी के लिए सीसीटीवी का व्यापक प्रयोग।
- (ix) क्षेत्रीय रेलों द्वारा बारी-बारी से विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर साप्ताहिक गहन स्वच्छता अभियान शुरू किए गए हैं।
- (x) रेलों के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न थीम आधारित अभियान शुरू किए गए हैं।

Installation of escalators and lifts at railway stations

†*20. DR. SATYANARAYAN JATIYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the planning and action plan to install escalators and lifts for smooth access to platforms of major railway stations, including Ujjain, Ratlam, Indore, Bhopal (Main), Itarsi, Nagpur, Jaipur and Kota; and

(b) the details of measures taken towards relieving the pressure of constantly growing passenger volume at aforesaid railway stations and the details of efforts being continuously made to increase cleanliness and passenger facilities at the said stations?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI SURESH PRABHU): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

† Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

(a) Indian Railways plan to provide about 770 No. of escalators and about 620 No. of lifts out of which so far, about 370 No. of escalators at 167 stations and about 183 No. of lifts at 98 stations have been installed across Indian Railways at major railway stations including Ujjain, Ratlam, Indore, Bhopal (Main), Itarsi, Nagpur, Jaipur and Kota as per the details below:

Sl. No.	Railway Station	Already installed		Planned/work in progress	
		Escalators	Lifts	Escalators	Lifts
1.	Ujjain	—	4	2	—
2.	Ratlam	2	—	—	2
3.	Indore	—	1	6	1
4.	Bhopal (Main)	2	1	—	2
5.	Itarsi	—	2	2	—
6.	Nagpur	2	—	4	—
7.	Jaipur	4	1	2	3
8.	Kota	2	2	—	—

(b) To ease out the pressure of constantly growing passenger volume at aforesaid stations, Railways have been continuously upgrading stations under its various Station Development Schemes. Ujjain, Ratlam, Indore, Itarsi and Jaipur are identified under Adarsh Station Scheme.

At these Adarsh Stations, following facilities are provided to tackle the growing passenger traffic:

- Improvement in the circulating area so as to ensure proper entry and exit of vehicles etc.
- A lighting tower for improved illumination.
- Improved modern lighting arrangements at platforms, concourse etc.
- Good passenger guidance system including signages and coach indication boards.
- Improvement of booking and enquiry offices.
- Lighting of booking office, the queuing area etc.
- Focus on quick entry and exit for passengers (minimum two entry and two exit points with booking office).
- Smooth access to station premises.
- Provision of wide Foot Over Bridges (FOBs).

All Minimum Essential Amenities have already been provided at the above stations as per the laid down norms. However, upgradation of passenger amenities is a continuous process and works are undertaken depending upon need, volume of passenger traffic etc.

To improve cleanliness at the stations, Special Cleanliness Campaign under Swachh Bharat Abhiyan was launched on Indian Railways on 2nd October, 2014. Regular intensive campaigns/drives have been organized since then over the Indian Railways with the sole objective towards significant and sustainable improvements in cleanliness standards of Trains and Railway premises, including Railway stations. Some of the major initiatives taken by Indian Railways towards sanitation/cleanliness are as follows:

- (i) Pace of fitment of bio-toilets in coaches has been increased. More than 25000 bio-toilets were fitted in the last two years and target for this year is 30,000. Fitment of Bio-toilets in coaches will prevent discharge of human waste during train journeys directly onto the track.
- (ii) The facility of On-Board Cleaning has been extended to more than 780 trains which is being monitored through a closed loop 'APP' based passenger feedback system.
- (iii) Railways is resorting to SMS-based, web-based and APP-based complaint redressal system. Daily IVRS-based passenger feedback is randomly being taken from about 1 lakh passengers.
- (iv) To assess the impact of cleanliness efforts at major stations, a third party survey on cleanliness indicators has been done at 407 stations this year generating 1.3 lakh passenger responses.
- (v) Integrated Housekeeping Contracts are being put in place at major stations progressively to promote use of Mechanised Cleaning equipment and Quality materials.
- (vi) Additional toilets at Railway Stations including Pay and Use toilets.
- (vii) Enforcement of Indian Railways (Penalties for activities affecting cleanliness at railway premises) Rules, 2012 has been intensified.
- (viii) Extending use of CCTVs for monitoring cleanliness activities at major stations.
- (ix) Weekly intensive cleanliness drives have been undertaken at various Railway stations in rotation by Zonal Railways.
- (x) Various theme-based drives have been undertaken from time to time with focus on cleanliness in different areas of Railways.

डा. सत्यनारायण जटिया: माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्टेशनों पर जनता के आवागमन की सुविधाओं के बारे में विस्तार से क्या काम किया जा रहा है तथा उनमें उज्जैन, रतलाम, इन्दौर, भोपाल, इटारसी, नागपुर, जयपुर और कोटा के कुछ स्टेशंस का नाम देकर उनके बारे में कहा है। मुझे खुशी है कि माननीय रेल मंत्री जी ने अपने इस उत्तर में इसका हवाला दिया है कि वे कहां escalator स्थापित कर रहे हैं और कहां लिफ्ट लगा रहे हैं। वैसे भी मैं रेल मंत्री जी को नए बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, उनके अन्तर्गत इन सारी योजनाओं को पूरा करने की संभावना को देखते हुए बधाई देता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि आदर्श स्टेशंस के अन्तर्गत जो स्टेशंस लिए गए हैं, वहां इस अवधारणा, इस concept को पूरा करने में कितना समय लगेगा और इसके लिए क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं?

श्री सुरेश प्रभु: सर, यह सही है कि हम लोगों ने बड़े पैमाने पर आम आदमी की सुविधाओं का ध्यान रखने की कोशिश की है, खास तौर पर बुजुर्गों और दिव्यांगों को जो दिक्कतें आती हैं, उनके लिए अतिरिक्त सुविधाएं देने का प्रबंध शुरू किया है। उनके लिए लिफ्ट और एस्केलेटर्स की सुविधा दी जाएगी, जो स्वाभाविक तौर पर बहुत बड़ा और अहम काम है। हम लोगों ने 770 एस्केलेटर्स लगाने की योजना बनाई है और जल्दी ही उनको लगाए जाने की शुरुआत की जाएगी।

जैसा माननीय सदस्य ने पूछा, यह बात बिल्कुल सही है कि सभी स्टेशनों में लिफ्ट और एस्केलेटर्स लगाया जाना बहुत जरूरी है, लेकिन शुरू में 'ए-वन' कैटेगरी, 'ए' कैटेगरी और 'सी' कैटेगरी के स्टेशंस के ऊपर ज्यादा जोर देकर हम लोगों ने काम की शुरुआत की है। शायद आपको मालूम होगा कि 75 स्टेशंस 'ए-वन' कैटेगरी में आते हैं, 302 स्टेशंस 'ए' कैटेगरी में आते हैं और 483 स्टेशंस 'सी' कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ इनमें से कुछ स्टेशंस को आदर्श स्टेशंस की कैटेगरी में भी चुना गया है, आपने इसके संबंध में पूछा भी है। सभी आदर्श स्टेशंस पर अभी ये सुविधाएं देने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए जो धन लगता है, वह passenger amenities के अंतर्गत आता है। पिछले कुछ समय से ही हमने passenger amenities को बढ़ाने की शुरुआत की है। इसके लिए पिछले तीन साल से करीब 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा दिया जा चुका है। हमें यह भी पता है कि यह धन भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लोगों की मांग ज्यादा है, इसलिए इसको देखते हुए हमने CSR के तहत भी कुछ कंपनियों से अपील की थी। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि कुछ कंपनियों ने आगे आकर इस काम के लिए हमें बहुत बड़ी मदद भी की है, जैसे WCL ने हम लोगों को 30 करोड़ रुपये दिए हैं। इससे हम लोग कैटेगरी 'सी' के स्टेशंस में भी इस तरह की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे एक यह अपील करूंगा, जैसे कि कुछ सांसदों ने ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Just answer his question.

SHRI SURESH PRABHU: His question was: How soon will I be able to fulfil it? I am saying, it depends upon the availability of resources. That is why passenger amenities have been stepped up. We are getting CSR funds. There are a lot of hon. Members who have given ₹ 5 crores each from their contribution. So, if you can also contribute, I will be very happy to do it.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, second question.

डा. सत्यनारायण जटिया: माननीय सभापति जी, बात यह है कि जो मॉडल स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, उन मॉडल स्टेशंस के काम को पूरा करने के लिए हमें कोई न कोई लक्ष्य तो रखना ही पड़ेगा। हम पुराने स्टेशंस में छोटे-बड़े बदलाव करके, वहां कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवा दें, केवल इससे तो ये बातें पूरी नहीं होंगी। नए प्रकार से उसकी रचना करके इस काम को करना होगा।

महोदय, नागदा का जो स्टेशन है, वह बड़े औद्योगिक क्षेत्र में आता है। उसके दोनों छोरों पर, एक तरफ इंडस्ट्री है और दूसरी तरफ शहर बसा हुआ है, इसलिए उन दोनों छोरों पर सुविधाओं का विकास करने की आवश्यकता है। नागदा जंक्शन एक एक बड़ा स्टेशन है।

स्वच्छता अभियान के बारे में मैं यह पूछना चाहता हूं, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर दी गई है। यह स्वच्छता अभियान हमारे लिए सभ्य समाज की ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please ask your question.

डा. सत्यनारायण जटिया: मेरा क्वेश्चन सीधा है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्टेशंस को साफ-सुथरा रखने एवं अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या आपने अभी तक कोई कार्यक्रम बनाया है? यदि बनाया है, तो आप उसकी कार्य योजना को कैसे पूरा करेंगे? आज भी स्टेशंस पर बहुत सारी असुविधाएं होती हैं, जिनको दूर किए जाने की जरूरत है।

MR. CHAIRMAN: That is a specific question. It can be answered specifically.

श्री सुरेश प्रभु: सर, इन्होंने दो बिन्दुओं पर अपना प्रश्न पूछा है। एक तरह से इसमें हम लोग incremental हैं। जिन स्टेशंस पर कोई सुविधा नहीं थी, वहां सुविधाएं देने की शुरुआत की गई है, लेकिन साथ-साथ स्टेशन को पूरी मात्रा में redevelop करने का कार्यक्रम भी हमने शुरू किया है। कुछ स्टेशंस पर काम शुरू कर दिया गया है और बाकी के स्टेशंस में भी आने वाले कुछ दिनों में काम शुरू हो जाएगा। कई स्टेशंस के लिए on bidding इस काम को शुरू किया गया है, ये स्टेशंस airport से भी ज्यादा अच्छे होंगे। इस तरह हम लोगों ने bidding करवाने के काम की शुरुआत भी की है। मुझे विश्वास है कि जिन सुविधाओं की बात आप कह रहे हैं, all stations will be fitted with all modern amenities.

स्वच्छ रेलवे का जो अभियान है, उसके तहत बहुत सारे बिन्दु आते हैं। पिछले दो सालों में 25,000 बॉयो-टॉयलेट्स लगाए गए हैं और इस वर्ष के लिए हमारा टारगेट 30,000 बॉयो-टॉयलेट्स बनाने का है। इसके साथ ही ऑन-बोर्ड क्लीनिंग की सुविधा की शुरुआत भी की गई है। 780 गाड़ियों में closed loop 'App' द्वारा इसकी निगरानी रखी जा रही है। हर रोज 1 लाख लोगों से online passenger feedback लिए जा रहे हैं, while they are still travelling. Third-party feedback भी लिए जा रहा है, अभी तक 1.3 लाख लोगों से ये लिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त mechanised cleaning equipments लगाए जा रहे हैं, additional toilets लगाए जा रहे हैं, सीसीटीवी से cleaning monitor करने की शुरुआत भी हमने की है। इस तरह कुछ और भी बिन्दु हैं, जिनके ऊपर मैं मानता हूं कि अधिक से अधिक लोगों के सहयोग से हम और ज्यादा काम कर पाएंगे।

DR. NARENDRA JADHAV: The hon. Minister's response is very comprehensive and informative. It talks about improvement in railway stations, bridges, lifts, even CCTVs, and cleanliness etc. Regrettably, however, the response does not say anything about making the railway stations physically disabled-friendly, *divyang*-friendly. Mr. Chairman, Sir, Suburban Railway travel in cities like Mumbai, is generally a torture. Mr. Sachin Tendulkar, who is here, will bear me out but, for physically disabled, it is nothing but a nightmare. Sir, I would like to raise a supplementary question. What are the provisions which the Government is coming up with to make the railway stations disabled- friendly? Is there a target date by which the projects are going to be completed? Is there a time-bound programme? Sir, I will take only 30 seconds. This is a low-cost improvement which will go a long way in alleviating the extreme difficulties currently faced by the disabled, *divyangs*, as well as senior citizens.

SHRI SURESH PRABHU: Sir, I fully share the compassion and the concern of the hon. Member. It is absolutely relevant to know that we are working on this very important issue. This is absolutely right that most of the stations, till recent past, were not disabled-friendly, inaccessible to many people and, therefore, to make all stations *divyang*-friendly is our objective, but it will begin in small steps. All new stations and all new coaches which are getting constructed will be *divyang*-friendly. We have already set the target. I will not be able to give the number just now because right now this is under trial. I will definitely share it with you. But the whole idea is, all the major stations, wherever there is a need for it, we are trying to make them *divyang*-friendly. All new stations are planned like that and all new coaches are already planned as *divyang*-friendly coaches. And, in fact, we have invited some experts in this field to understand as to how the design should be and, therefore, we are really working on it.

श्री माजीद मेमन: माननीय सभापति जी, माननीय रेल मंत्री जी से अभी हमारे एक मित्र ने मुम्बई के बारे में पूछा। बदकिस्मती से रेल का बजट अलग से नहीं रखा गया, नहीं तो विस्तार से हम कई सवाल उनसे पूछ सकते थे, लेकिन चूंकि अब मौका है, इसलिए मैं इस प्रश्न से जुड़े हुए विषय के बारे में माननीय रेल मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं और वे इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि मुम्बई शहर की लोकल ट्रेनों की परिस्थिति, जिसके बारे में अभी हमारे मित्र श्री नरेंद्र जाधव जी ने कहा, वह ऐसी है कि अगर कोई लोकल ट्रेन 30 या 45 सेकंड भी लेट हो जाती है, तो पीक टाइम में ऐसी अवस्था होती है कि प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर्स को खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती है।

महोदय, जहां तक एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स के प्रावधान की बात है, मुझे लगता है कि मुम्बई में ऐसी परिस्थिति हो चुकी है कि लगभग सभी रेलवे स्टेशनों पर या तो लिफ्ट या एस्केलेटर का प्रोविजन होना चाहिए। Disabled commuters, elderly commuters, women and sick commuters are finding it very difficult to climb from one platform to another when

the announcements are made that the train is coming say on platform No. 5 instead of platform No. 3. सर, यह बहुत आवश्यक है। मैं रेल मंत्री जी का आभार मानता हूँ कि उन्होंने पिछले वर्ष में जनरल मैनेजर्स सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे की, खासदारों यानी सांसदों के साथ मीटिंग रखी थी। मगर उसके फलस्वरूप कुछ हो नहीं पाया। आपका अलग बजट नहीं आया। हमारी बड़ी आशाएं थीं कि आप मुम्बई के लिए बहुत कुछ देंगे, ताकि मुम्बई के कम्प्यूटर्स को सुविधाएं मिलें।

श्री सुरेश प्रभु: सर, हमारे सम्माननीय सदस्य बहुत जाने-माने एडवोकेट हैं। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुम्बई के लोगों की समस्या हमारे सामने रखी है और उन्हें जानकर खुशी होगी कि देश के इतिहास में शायद पहली बार एक शहर के लिए 55 हजार करोड़ रुपये की, अपग्रेडेशन ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजना हमारे सम्माननीय प्रधान मंत्री जी की उपस्थिति में दिसम्बर, 2016 में यानी लगभग पांच हफ्ते पहले हम लोगों ने लॉच की थी। उसमें एलिवेटेड कॉरिडोर भी है। उसमें हमारा मुम्बई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट-तीन भी है और उसमें 55 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के बाद, मुझे विश्वास है कि लोगों की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। इस बारे में बजट में भी लिखा है। जब उन्हें बजट की पूरी जानकारी मिलेगी, तब वे इससे अवगत हो जाएंगे।

महोदय, मुम्बई में लिफ्ट्स लगाने के लिए, जैसा मैंने कहा, आपको सुनकर खुशी होगी कि हम लोगों ने 30 करोड़ रुपये सिर्फ सीएसआर के तहत डब्ल्यूसीएल से लिए हैं और उसमें 33 स्टेशन्स जिनमें अलग-अलग स्टेशन्स हैं, यानी सेंट्रल रेलवे के 19 स्टेशन्स हैं और वेस्टर्न रेलवे के 14 स्टेशन्स हैं, उनके ऊपर काम करने की शुरुआत हुई है। कुछ टेंडर्स भी इश्यू किए गए हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इससे भी लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ कि मुम्बई में जिस तरह से ट्रैफिक का लोड बढ़ रहा है, वहां 75 लाख लोग रोज ट्रांसपोर्ट सबअर्बन सिस्टम का यूज करते हैं और उसमें पिछले 40-50 साल में परिवर्तन नहीं हुआ। इसके लिए एलिवेटेड कॉरिडोर और इन्फ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन करने की जरूरत है। इसके लिए हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। आपके सहयोग के लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्रीमती विप्लव ठाकुर: माननीय सभापति जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूँगी कि दिल्ली स्टेशन पर आपने एस्केलेटर लगाया हुआ है, जो फर्स्ट नम्बर प्लेटफॉर्म पर जाता है, लेकिन उसके बाद प्लेटफॉर्म-2, प्लेटफॉर्म-3, प्लेटफॉर्म-4 या प्लेटफॉर्म-5 पर लोगों को सीढ़ियां उतर कर जाना पड़ता है। जो ओल्ड हैं, सीनियर सिटिजंस हैं या जिस तरह से इन्होंने कहा हैंडिकैप्ड लोग हैं, उनको वहां जाने के लिए अपना सामान उठाकर उन सीढ़ियों से उतरना और चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यह जो आपका प्रोग्राम है, इसे आप पहले दिल्ली में क्यों नहीं शुरू करते, जहां पर सारे भारत के, सारी दुनिया के लोग आते हैं और उन सीढ़ियों से उतरना और चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है? तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि उसके लिए ये क्या प्रावधान करने जा रहे हैं?

श्री सुरेश प्रभु: सर, जैसा मैंने कहा कि सब जगहों पर A, A Plus and C category में हम लोग एस्केलेटर्स लगाने जा रहे हैं। जैसे नयी दिल्ली स्टेशन लीजिए, यह बिल्कुल सही है कि उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। यदि हम एक ही स्टेशन पर सभी प्लेटफॉर्म्स पर इसे लगाएँगे, तो हमारे पास जो मर्यादित मात्रा में धन उपलब्ध है, उससे शायद वह कुछ स्टेशंस पर ही लगेगा।

हम यह कोशिश कर रहे हैं कि पूरी मात्रा में ज्यादा से ज्यादा स्टेशंस पर यह लगे। यदि हमें धन उपलब्ध होगा, ...(व्यवधान)... यह आप भी जानते हैं कि रेल की फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, उसके बाद भी, जैसा मैंने आपको बताया कि कितनी बड़ी मात्रा में हम लोगों ने उसमें बढ़ोतरी भी लाई है। यह बिल्कुल सही है कि सभी प्लेटफॉर्म्स पर यह लगना चाहिए। मैं भी यह मानता हूँ, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि पिछले ढाई सालों में जितने एस्केलेटर्स लगे हैं, उनकी मात्रा अगर आप देखें, तो ढाई साल पहले वे कितने थे और कितनी बड़ी मात्रा में लगे हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए. ...(व्यवधान)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर: सर, ...(व्यवधान)...

Better internet service to the household consumers

*21. SHRI SAMBHAJI CHHATRAPATI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the BSNL/MTNL broadband internet connection, availed by household consumers, works at a very slow speed and remains erratic with the result that people have no choice but to opt for private internet connection;

(b) the major reasons for this state of affairs when the country is so capable in satellite technology; and

(c) whether Government has any concrete plan to make BSNL/MTNL internet services efficient and faster?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE; AND THE MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) No Sir, the speed of Broadband connections is provided as per tariff plans opted by the household customers. After the expiry of the fair usage limits, as per tariff plan opted the speed falls back to the level as defined in the plan. After Fair Usage Policy (FUP) customer has an option to restore the pre-FUP speed by making additional payment. Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) has increased the FUP limit (speed) from 512 Kbps (Kilo-bytes per second) to 1 Mbps (Mega-bytes per second) from 01.08.2016 without any additional cost to customer to provide better speed experience to customer.

The speed mentioned in any tariff plan is the maximum speed that a customer can get. A customer may get lesser speed at some point of time depending upon following factors: